

□□□□□□□□ □□□□

जनसत्ता 11 अगस्त, 2014 : बरसों पहले □ कदफे हदुस्तान की □ कवख्यात वदुषी के साथ खाने की मेज पर गपशप करते वक्त मुझे जोर क झटक लगा था□

बातचीत के बीच मेरे मुंह से नक्का क मैं हदी और अंगरेजी दोनों भाषाओं में लिखता हूँ□ इस पर वदुषी की राय थी क शैक्षणिकलहाज से हदी में लिखना ठीक है□ मैंने तपाकसे कहा क मैं तो अपने कुछ लेख मूल रूप से हदी में ही लिखता हूँ, उन्होंने मुझे वसिफरति आंखों से देखा और अचरज से बोली क 'हदी या तमलि जैसी भाषा□' गली-मुहल्ले की बातचीत केला□ ठीक है लेकिन इन भाषाओं में वैसा गंभीर चतितन नहीं किया जा सकता जैसा क फ्रेंच या अंगरेजी में□' जाहरि है, इतना सुनने के बाद उनके साथ भोजन क स्वाद मेरे ला□ थो□ क वा हो गया□

मेरे मन के किसी कोने में यह बातचीत अभी तक बैठी रह गई है क्योंकि अंगरेजी भाषा में लिखने-प□ ने वाले ज्यादातर लोग जसि चीज के स्वयंसदिध मान कर चलते हैं वह इस बातचीत में □ क झटके में उजागर हो गई थी□ भारतीय भाषाओं को हीन समझा जाता है, और इसी तरहसे उन लोगों को भी हीन माना जाता है जो इन भाषाओं में लिखते-प□ ते और बोलते हैं□ नस्ली और लैंगिक गैर-बराबरी की तरह भाषागत भेदभाव भी कुछ इतना जाहरि और आमपहम है क हम इसे सहज मान लेते हैं□

यूपी□ ससी की सविलि सेवा परीक्षा के सीसैट परचे को लेकर उठे विवाद के मूल में है भाषाई गैर-बराबरी क सवाल□ पछिले डे□ महीने से और खासतौर पर पछिले हफ्ते भर में इस विवाद पर आई प्रतिक्रियाओं से भाषाई भेदभाव की इस जानी-पहचानी राजनीति की पुष्टि होती है□ बिना प्रदर्शनकारियों की मांगों के समझे, बिना तथ्यों की जांच क□ अंगरेजी क मीडिया सीसैट-वरीधी आंदोलन पर पलि प□ है□ उधर जनप्रतिनिधियों के शरमाशरमी इस सवाल पर बोलने के मजबूर होना प□ रहा है□ विवाद के अंगरेजी बनाम हदी और हदी बनाम अन्य भारतीय भाषाओं के फंदे में फंसाने की केशशि हो रही है□ सत्ताधारी दल के नेता च□ याली आंसू बहा रहे हैं लेकिन सरकार राज्यसत्ता के चरतिर के अनुरूप आचरण कर रही है□ सीसैट विवाद पर हुई सरकारी घोषणा से लग सकता है क चलो आखरि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के वरीधी की सुध तो ली, लेकिन अगर यह सुध लेना है तो फरि बेसुध होना कसे कहते हैं? सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राहत के तौर पर वह दिया है जो उन्होंने मांगा ही नहीं था□ प्रदर्शनकारी यह थो□ ही मांग कर रहे हैं क सीसैट के परचे में पूछी गई अंगरेजी के अंकों की गणना मेरटि लसिट में आप न करें!

सीसैट के वरीधी युवाओं में असल मुद्दों के लेकर वचारों की स्पष्टता कहीं ज्यादा है, हालांकि बात के और भी ज्यादा धारदार बना कर रखा जा सकता था□ वरीधी □ प्टीट्यूड टेस्ट के लेकर क्तिई नहीं है, हालांकि सीसैट के वरीधियों में से कुछ की बातों से ऐसा लग सकता है□ किसी नौकरी केला□ केई उम्मीदवार कतिना उपयुक्त है- इसे जांचने केला□ पूरी दुनिया में □ प्टीट्यूड टेस्ट क उपयोग □ कमानकके रूप में किया जाता है□ हां, इस बात पर बहस जरूर हो सकती है क किसी प्रशासककेला□ आवश्यकयोग्यताओं में कनि-कनि बातों के किस मात्रा में शामिल किया जाय□ ठीक इसी तरह मानवकी बनाम वजिज्ञान के विवाद में कुछ दम तो है जरूर लेकिन यह भी मुद्दे की मुख्य बात नहीं है□ यह बात सच है क जो छात्र इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की प□ आई से जु□ है वे बाकियों की तुलना में इधर कई साल से सविलि सेवा परीक्षा में अच्छा परणाम ला रहे हैं□ हो सकता है, ऐसे उम्मीदवार जसि तरह के परीक्षा पैटर्न से

परचिति है वह सविलि सेवा परीक्षा के पार करने के मामले में उनके लिए तनकि मददगार साबति होता हो

सीसैट के लेकर उम। वरिध न तो हदि की तरफदारी में है और न ही अंगरेजी की मुखालफत में। प्रदर्शनकरियों ने जोर-शोर से कहा है कि वे हदि की हमियात में यह सब नहीं कर रहे बल्कि उनका संघर्ष सभी भारतीय भाषाओं का पक्षधर है। प्रदर्शनकरियों ने बार-बार कहा है कि वे अंगरेजी के वरिध में नहीं हैं। अंगरेजी भाषा संबंधी योग्यता की जांच वाले परचे का वे वरिध नहीं कर रहे। अंगरेजी मीडिया यह बात समझ ही नहीं पा रहा कि हदि-हमियाती या फिर अंगरेजी-वरिधी हुआ। बगैर भी कोई भाषाई गैर-बराबरी के सवाल के उठा सकता है।

यह वरिध-प्रदर्शन अंगरेजी के खिलाफ नहीं बल्कि अंगरेजी के दबदबे के खिलाफ है। राष्ट्र की सारी प्रतभा अंगरेजी भाषा। कछोटे-से समूह के अंदर ही वरिजती है- यह वरिध-प्रदर्शन इस धारणा के खिलाफ है। यह हदि की हमियात का नहीं बल्कि अंगरेजी के बरक्स बाकी भारतीय भाषाओं के हो। के लिए बराबर की जमीन दिलाने की ल।ई है। सीसैट के परचे के खिलाफ इस सीधे-सादे मगर तूल पक।ते वरिध-प्रदर्शन की ज।में है इस देश में अनौपचारिक रूप से जारी वह भाषाई भेदभाव जो किसी रंगभेद से क्ताई कम नहीं।

बात यह है कि सीसैट ब।चुप्पा ढंग से अंगरेजी को बुलंद बनाता है।।प्टीट्यूड टेस्ट के भीतर नश्चिति ही भाषाई योग्यता-क्षमता की जांच होनी चाहिए।।लेकिन क्या इस बात का भी कोई तुक है कि भाषाई योग्यता-क्षमता की जांच सरिफ अंगरेजी भाषा में हो? सीसैट में फलिहाल यही व्यवस्था है। यह अलग बात है कि सीसैट में भाषाई योग्यता की जांच के लिए।पूछी जाने वाली अंगरेजी दसवीं-बारहवीं के स्तर की होती है। यहां मुद्दे की बात यह है कि।प्टीट्यूड टेस्ट में भाषाई योग्यता की जांच के लिए।किसी भारतीय भाषा पर वचिर तक नहीं किया गया है। सीसैट के प्रश्नपत्र में प्रस्तुत अनुवाद के लेकर उठा हंगामा बेजा नहीं है। इससे साबति होता है कि।प्टीट्यूड की जांच भाषा-नरिपेक्ष नहीं है।

प्रदर्शनकारी ठीक ही नाराज हैं कि उनके साथ सविलि सेवा की परीक्षा में दोगम दर्जे के परीक्षार्थी की तरह बरताव किया जा रहा है। अंगरेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का दर्जा कुछ वैसा ही है जैसा कि घरेलू मैदान पर खेलने वाली टीम या फिर टेनिस या बैडमिंटन में वरियता प्राप्त खिला।थिों का होता है, जबकि भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रतीक्षा करनी होती है कि कश, कोई कश्मा होता और वाइल्डकार्ड।ट्री मलि जाती। सीसैट के वरिध में प्रदर्शन करने वाले उस अन्यायी शक्ति-समीकरण से जूझ रहे हैं जिसे वस्तुनश्ठि यानी भेदभाव से परे मानी जाने वाली परीक्षा-पद्धति के भीतर ही गूंथ दिया गया है।

आंकी। इस आशंका के पुष्ट करते हैं। बीते तीन दशकों में भारतीय भाषा के उम्मीदवारों की संख्या सविलि सेवा में ब।थी और आभजित्य मानी जाने वाली इस सेवा के दरवाजे साधारण सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। खुले थे। सविलि सेवा परीक्षा की नई पद्धति साल 2011 में शुरू हुई और इस शुरुआत के साथ बीते तीन दशकों का रुझान उलट गया। 2008-10 के बीच भारतीय भाषाओं के माध्यम बना कर सविलि सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या चौवालीस प्रतिशत थी जो 2011-12 में घट कर महज अठारह प्रतिशत रह गई। हालांकि 2013 के लिए। औपचारिकतौर पर आंकी। उपलब्ध नहीं है तो भी कहा जा सकता है कि सविलि सेवा परीक्षा के लिए। भारतीय भाषाओं के माध्यम बनाने वाले उम्मीदवारों की स्थिति पहले की तुलना में बदतर ही हुई है। खबरों के मुताबिक अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों में हदि माध्यम के उम्मीदवारों की संख्या तीन प्रतिशत रह गई है जबकि 2009 में यह संख्या पच्चीस प्रतिशत थी।

दरअसल, सीसैट का परचा या फिर सविलि सेवा परीक्षा तो। कब। सच्चाई का सरिा भर है। उच्च शिक्षा की पूरी प्रणाली भारतीय भाषाओं के प।ई और परीक्षा का माध्यम बना कर स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले वदियार्थियों के वरिध में ख। है। देश में उच्च अध्ययन के नामी-गरामी संस्थानों में

प्रवेश के लिये उन्हें आनन-फानन में अंगरेजी अपनानी पड़ी थी है। समाज विज्ञान और मानविकी के विषयों के पढ़ाई वाले छात्रों के लिये यह केशशि कुछ इतनी कठिनी साबति होती है कि बहुधा छात्र इस आजमाइश में ही नहीं पड़ते। अगर संस्थानों को कया पकसे अधिक भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की अनुमति देने वाला हुआ तो भी हर कदम पर बाधा खड़ी मलिती है: पाठ्यक्रम और उनमें दर्ज जरूरी क्तिबें अंगरेजी में होती है, प्रश्नपत्र भले ही 'ज्जानी गूगल जी' के सहारे अन्य भाषाओं में अनुदति करवा लिया जाय लेकिन शायद ही कोई परीक्षक इन भारतीय भाषाओं को जानकर मलित है। भारतीय भाषा के पढ़ाई को माध्यम बनाने वाले छात्र अपेक्षाकृत कमतर माने जाने वाले संस्थानों में दाखला ले पाते हैं या फिर बेहतर संस्थानों के भीतर कमतर दर्जे के अकदमिकपद को हासल कर पाते हैं। उन्हें हर क्वत्त धारा के वरिद्ध तैरना पड़ता है। सविलि सेवा परीक्षा के खलिफ होने वाला प्रदर्शन उस पूरी व्यवस्था के खलिफ प्रदर्शन है जो भारतीय भाषाओं में पढ़ाई-लिखाई करने वाले के वरिद्ध खड़ी है।

सरकार के अल्पकालिक बेबसी के तरक झूठे हैं। अगर सरकार समस्या को लेकर गंभीर है तो तीन घोषणाएं तुरंत कर सकती है। एक प्रारंभिक परीक्षा की तारीख को कुछ हफ्तों के लिये आगे खसिक दिया जाय ताकि पछिले छह हफ्तों से अनश्चित्य से जूझ रहे परीक्षार्थियों को तनकितैयारी का समय मल्लि दो, कम से कम इस साल के लिये सीसैट परीक्षा के अंकों को मेरिट के लिये जोड़ना नहीं चाहिये, इस परचे को पास करने के लिये न्यूनतम जरूरी अंकों के तय कर दिया जाय और जो इतने अंकला उसे इस परचे में पास माना जाय। तीन, सरकार इस हकीकत को स्वीकर करे कि सविलि सेवा परीक्षा भाषा-नरिपेक्ष नहीं है, वह भेदभाव करती है और अगले साल तक इस भाषाई भेदभाव को खत्म करने के लिये सरकार को कनई व्यवस्था बनाने का आशवासन दे।

सीसैट वरिधी आंदोलन भाषाई भेदभाव के खलिफ उपजे आक्रोश का आंदोलन है। इसी वजह से मैं इस वरिध-प्रदर्शन को देख कर खुश हूं और उसे सलाम भेजता हूं। वरिध-प्रदर्शन अगर मुख्य मुद्दे से न भटके, सविलि सेवा परीक्षा देने का एक और अतरिक्त्त मौक जैसे फुसलावनों या फिर सत्ताधारी पार्टी और उसके जेंटों के फंस-फंदों में न उलझे तो फिर यह वरिध-प्रदर्शन देसी भाषाओं के खलिफ जारी रंगभेदी बरताव के असर को क हद तक कम करने की दशा में बड़ा कदम साबति हो सकता है। और हां, एक बात यह भी कि ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते!

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिये क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिये क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>